भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 1380

उत्तर देने की तारीखः 11.02.2025

नशीली दवाओं की मांग में कमी के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना

1380. श्री प्रद्युत बोरदोलोई:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) नशीली दवाओं की मांग में कमी के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीडीडीआर) के तहत योजना की शुरूआत से लेकर अब तक असम में सहायता प्राप्त परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इनकी वर्षवार संख्या कितनी है;

(ख) एनएपीडीडीआर के तहत सर्वाधिक संवेदनशील जिलों को चुनने के लिए मानदंड क्या हैं;

(ग) एनएपीडीडीआर के तहत असम में सबसे अधिक संवेदनशील जिलों में से प्रत्येक जिले को कितनी धनराशि आवंटित और उपयोग की गई है; और

(घ) असम के नागांव जिले में प्रति लाख जनसंख्या पर नशे की लत से ग्रस्त लोगों के लिए एकीकृत पुनर्वास केंद्रों (आईआरसीए), आउटरीच और ड्रॉप-इन केंद्रों (ओडीआईसी) और जिला नशा मुक्ति केंद्रों (डीडीएसी) की संख्या कितनी है और एनएपीडीडीआर द्वारा कवर किए गए जिलों में इसका औसत क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री बी.एल. वर्मा)

(क): असम में नशीली दवाओं की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीडीडीआर) के तहत इसकी शुरूआत से लेकर अब तक सहायता प्राप्त परियोजनाओं की संख्या निम्नानुसार है:

वर्ष	सहायता प्राप्त परियोजनाओं की संख्या
2019-20	23
2020-21	34
2021-22	30
2022-23	24
2023-24	23

(ख): देश भर के सभी जिले एनएपीडीडीआर योजना के अंतर्गत शामिल हैं।

(ग): पिछले पांच वर्षों के दौरान एनएपीडीडीआर योजना के अंतर्गत राज्य कार्य योजना के तहत असम को 5.04 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं और असम में नशा मुक्ति केंद्र चलाने के लिए गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को 27.10 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

(घ): असम के नागांव जिले में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा एनएपीडीडीआर योजना के अंतर्गत एक जिला नशा मुक्ति केंद्र को सहायता दी जा रही है।

वर्तमान में, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा असम में सोलह (16) एकीकृत नशामुक्ति पुनर्वास केंद्रों (आईआरसीए), तीन (3) समुदाय आधारित संगतिपरक इंटरवेंशन (सीपीएलआई) केंद्रों, तीन (3) आउटरीच और ड्रॉप इन सेंटर (ओडीआईसी) और नौ (9) जिला नशा मुक्ति केंद्रों (डीडीएसी) को सहायता दी जा रही है।

****